



ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2016; 2(12): 268-270
www.allresearchjournal.com
Received: 13-10-2016
Accepted: 17-11-2016

रेखा रानी

बी0 एड0 विभाग, किशोरी रमण
महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत।

राष्ट्र नेतृत्व का संकट

रेखा रानी

प्रस्तावना

हैं रौंद रहे मानवता को, यहाँ दुराचारी अत्याचारी
ये कैसा लोकतन्त्र लोगों, दुःखी घूम रही है प्रजा सारी।
अरबों-खरबों के होते भ्रष्टाचार, गरीबों पर पड़ती उसकी मार,
महँगाई दिन पे दिन बढ़ती, जनता में मचती हा-हाकार।

उपरोक्त पंक्तियों के द्वारा कवि हंसराज भारतीय वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था पर अपना विरोध प्रकट करते हुये सरकार की नाकामियों को उजागर करते हैं। भ्रष्टाचार, गरीबी, महँगाई, मॉबलिचिंग, बलात्कार, साम्प्रदायिक झगड़े, किसान आत्महत्या व शिक्षा केन्द्रों पर आक्रमण जैसे मुद्दों पर सवाल उठाते हैं। ऐसी स्थिति में देश का विकास कैसे सम्भव है। देश का नेतृत्व करने वाला इन अहम समस्याओं को नजर-अन्दाज कर रहा है। राष्ट्र का वर्तमान व भविष्य निर्धारित करने वाला सशक्त, कुशल और उत्साही नेतृत्व वाला होना चाहिए। यदि नेतृत्व मजबूत होगा तो देश का विकास अवश्यंभावी है, परन्तु इसके विपरीत यदि नेतृत्व ही कमजोर हो और तमाम विसंगतियों से युक्त हो तो वह सत्ता की कुर्सी पर बैठकर शासन तो कर सकता है परन्तु सक्षम नेतृत्व नहीं दे सकता। संसार के तमाम देशों ने विपरीत परिस्थितियों में रहकर भी विभिन्न क्षेत्रों में महारत हासिल की है और नये प्रतिमान गढ़े हैं। उन्नति और विकास के नए सोपानों को तय करते हुए शीर्ष ऊँचाइयों को हुआ है तो उसके पीछे उनका सुदृढ़ और सक्षम नेतृत्व है। ऐसा नेतृत्व जो सबकी सहभागिता सुनिश्चित करे, सभी को साथ लेकर चले सिर्फ आर्थिक ही नहीं हर क्षेत्र में समृद्धि की बात करे। अपनी कथनी व करनी में भेद न करे। अपितु अपने समाज के सामने एक उच्च आदर्श प्रस्तुत करें। ऐसा व्यक्ति ही राष्ट्र को नई दिशा प्रदान कर सकता है।

भ्रष्टाचार, जातिवाद, भाई-भतीजावाद, सम्प्रदायवाद, क्षेत्रवाद जैसी विपदाओं से युक्त नेतृत्व सिर्फ अपने लोगों की आर्थिक तरक्की का ही औजार बन सकता है, सम्पूर्ण राष्ट्र का विकास नहीं। यह दौर आत्ममुग्धता का नहीं है अपितु वर्तमान पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करने के साथ-साथ आने वाली पीढ़ियों हेतु संसाधनों और अवसरों को सहजकर रखने का है। लेकिन यहाँ तो सत्ता पाने की लालसा में किसी भी हद तक गिर जाते हैं। सिद्धान्त, विचारधारा और राष्ट्र उत्थान के नाम पर राजनीति करने वाला हर दल और हर एक राजनेता लोकतन्त्र के दामन पर दाग लगाता नजर आ रहा है। देश के सभी बड़े राजनैतिक दल खुद ही नेतृत्व को लेकर संकमणकालीन अवस्था में दिखते हैं। इसी का नतीजा है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दामों में भारी गिरावट के बावजूद बेलगाम महँगाई, दाल, सब्जी जैसी तमाम खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि, अन्नदाता किसानों द्वारा लगातार आत्महत्या, शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी जरूरी वस्तुओं व सेवाओं का लगातार महँगा होना, रोजगार विहीन सामाजिक व साम्प्रदायिक सद्भाव पर चोट, देश के बुद्धिजीवी वर्ग की अवहेलना जैसे तमाम कारण आज नेतृत्व के सामने खड़े हैं।

सत्ता में आ जाने के बाद हर कोई बड़ी लकीर खींचने के बजाय अपने पूर्ववर्तियों की आलोचना करके अपनी प्रासंगिकता सिद्ध करना चाहता है। सत्ता की चकाचौंध उन्हें आत्ममुग्धता के इस स्तर पर लाकर खड़ा कर देती है कि स्वयं को राष्ट्र के प्रति समर्पित न मानकर राष्ट्र को ही अपने प्रति समर्पित मानने का मोह पाल बैठते हैं। यही कारण है राजनैतिक नेतृत्व पर आया संकट राष्ट्र का संकट मान लिया जाता है राजनैतिक नेतृत्व का हित राष्ट्र का हित मान लिया जाता है जिस जनता की वदौलत वह सत्ता में आते हैं वही उनके लिए गौण हो जाते हैं।

वर्तमान में बाजार आधारित आर्थिक व मौद्रिक नीतियों ने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को धरासाई कर दिया है, देश के निर्धनों-वंचितों के लिए बुनियादी सुविधायें प्राप्त करना कल्पना मात्र हो गयी है।

Corresponding Author:

रेखा रानी

बी0 एड0 विभाग, किशोरी रमण
महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत।

जमाखोरी, कालाबाजारी, व कमजोर नियन्त्रण के कारण महँगाई आसमान छू रही है। आज का आलम यह है कि गली-मुहल्लों में टेले पर सब्जी बेचने वाले सब्जी का भाव किलो में न बता कर पाव में बताते हैं। जिन किसानों को अन्नदाता कहा जाता है आज वही सरकार की उपेक्षा के कारण खुद अन्न के लिए मोहताज बन गये हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक देश होने के बावजूद भी यहाँ लाखों लोग इससे महरूम हैं। गरीबों के लिए प्रोटीन व आयरन का सबसे बड़ा जरिया मानी जाने वाली दाल से लेकर हरी सब्जियाँ जैसी जरूरी चीजें उनकी थाली से गायब हो रही हैं। गरीब इनके अभाव में चटनी व प्याज से रोटी खा लेता था। आज उसका मूल्य सोना/चाँदी के तुल्य हो गया है। जो गरीब की पहुँच से दूर है। इस दौर में राष्ट्र का नेतृत्व कुछ इस तरह हो रहा है – डिजिटल इण्डिया और मोबाइल एप पर एक क्लिक के माध्यम से हर वस्तु और सेवा तक पहुँच की बात कर रहा है, वहीं देश के तमाम भागों में आज भी लोग स्वच्छ पानी पीने के लिए तरसते हैं। राजस्थान, व मध्य प्रदेश के कुछ गाँव – देहात ऐसे ही हैं जहाँ गड्डों में गन्दा पानी भरा हुआ रहता है। उसी को पीने के काम में लेते हैं। कोसों दूर जाने पर भी स्वच्छ व मीठा पानी उपलब्ध नहीं है। इस विज्ञान व प्रौद्योगिकी के युग में भी किसान खेत की मेड़ पर बैठ कर बादलों की बाट जोहता है, ताकि फसल अच्छी हो सके। भारत में आज भी कृषि मानसून पर निर्भर है। केन्द्र से लेकर राज्य सरकारें हर साल बजट में उद्योगपतियों के लिए करोड़ों रुपये की कर राहत देती है, पर स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों की बात सिर्फ चुनावी घोषणा पत्रों तक सीमित रह जाती है उसे धरातल पर लाने के लिए किसी सरकार ने पहल नहीं की।

विश्व आर्थिक मंच वर्ष 2016 में जारी मानव पूँजी सूचकांक में 130 देशों की सूची में भारत 105वें स्थान पर है। यह आश्चर्य का विषय है कि विश्व की तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था और विकास दर के बड़े-बड़े वादों के बावजूद मानव पूँजी सूचकांक में हम बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों सहित कई अफ्रीकी और खाड़ी देशों से पीछे है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित में डिग्री धारकों की संख्या 7-8 करोड़ है, जबकि चीन में इसकी संख्या 25 लाख के करीब है, लेकिन भारत ने अपनी मानव पूँजी का सिर्फ 57 फीसदी उपयोग किया है मानव पूँजी सूचकांक – का आधार किसी भी देश में अपने नागरिकों का पालन पोषण, शिक्षण – प्रशिक्षण, विकास और प्रतिभाओं का उपयोग होता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह सूचकांक हमें बताता है कि गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, बेरोजगारी, प्रदूषण, अशिक्षा जैसी तमाम समस्याओं से निजात पाने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना आवश्यक है। मात्र आर्थिक विकास दर में वृद्धि किसी देश की उन्नति और समृद्धि का पैमाना नहीं होता, शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी राष्ट्र के सम्पूर्ण विकास के लिए अनिवार्य तत्व हैं। आजादी के सात दशक बाद भी कई राज्यों में अभी तक शिक्षा व स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति नहीं बनी है। केवल कागजों पर नारे लगाये जाते हैं सभी को शिक्षा, स्वच्छ भारत – स्वास्थ्य भारत। जबकि शिक्षा के लिए सकल घरेलू उत्पादन का छः प्रतिशत व स्वास्थ्य के लिए चार प्रतिशत तक आवंटन सुनिश्चित होना चाहिए। ताकि सभी इसके दायरे में आ सकें। दुर्भाग्यवश हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का उद्देश्य मात्र आँकड़ों में वर्तमान विकास दर को बनाए रखना है, परन्तु विकास के नाम पर असमानता की खाई और भी गहरी होती जा रही है। विकास का उद्देश्य लाभ का उदारता से सभी में वितरण होना चाहिए, ताकि सामान्य जन भी लाभान्वित हो सकें, परन्तु यह विकास नीति तो धनिकों को और अधिक धनी और निर्धनों को और अधिक निर्धन बना रही है।

इस बिगड़ते माहौल के लिए राजनैतिक, प्रशासनिक नेतृत्व के साथ-साथ पूँजीपति वर्ग, धर्माचार्य, मठाधीसों व मीडिया भी

जिम्मेदार है। आये दिन बड़ी-बड़ी बातें करके देश की जनता को राष्ट्रीयता, इमानदारी, मितव्ययता, अनुशासन व कर्मठता तथा धर्म का पाठ पढ़ाते हैं पर कभी अपने गिरेवान में झाँकने की कोशिश की है लोकतन्त्र का चतुर्थ स्तम्भ कहा जाने वाला मीडिया भी इन कथित कर्णधारों द्वारा कही गई एक-एक बात को ब्रेकिंग न्यूज बनाकर देश की जनता को उबाता रहता है। वस्तुतः जनता की आवाज उठाने की बजाय मीडिया की प्राथमिकता सरकारी विभागों और कॉरपोरेट जगत से प्राप्त विज्ञापन हैं। जिन पर उनकी रोजी-रोटी टिकी हुई है। टीआरपी की होड़ में टीवी चैनल काइम, सेक्स, ज्योतिष, हास्य और पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित धारावाहिकों को बार-बार परोस रहा है।

राजनैतिक नेता, पूँजीपति व धर्माचार्य इन सबका एक ही निहित स्वार्थ है दुनिया की सारी सुख-सुविधाओं से परिपूर्ण इस वर्ग के पास परेशानी/कठिनाई जैसा शब्द फटक भी नहीं सकता। यह कारण है कि यह वर्ग यथास्थितिवाद का पुरजोर पक्षधर है। इन्हें किसी भी प्रकार का परिवर्तन पसन्द नहीं, चाहे आम जन भ्रष्टाचार, महँगाई, अकाल, भूखमरी, महामारी जैसी समस्याओं से ग्रस्त हों देश का पढ़ा-लिखा युवा वर्ग नौकरी की तलाश में बुढ़ापे तक पहुँच जाये, देश की एक तिहाई जनता गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करती रहे, पूँजीपति व उद्योगपति वर्ग साधारण जनता का शोषण करती रहे किसी पर कोई असर नहीं पड़ता। उनके लिए सिंहासन, 'गद्दी' ही सब कुछ है। यही उनका राष्ट्र है, देशभक्ति है, यही उनका उद्देश्य है बाकी चीजों के प्रति यह वर्ग अपनी संवेदनशीलता खो बैठा है। भारतीय संविधान भारत को एक लोकतान्त्रिक राष्ट्र घोषित करता है, सत्ता शीर्ष पर बैठे निर्वाचित जनप्रतिनिधि अपने चरित्र को लेकर हमेशा सुखियों में रहते हैं। अधिकतर नेताओं की सम्पत्ति करोड़ों – अरबों – खरबों में है। संसद व विधानसभाओं में आरोप-प्रत्यारोप की भाषा ही नहीं, बल्कि मारपीट व गाली-गलोज भी आम चीज बन गई है। हमारे अधिकतर जनप्रतिनिधि अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि के चलते जैसे भी सदैव चर्चा का विषय बने रहते हैं। अपराध का राजीनतिकरण हो रहा है या राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, कुछ भी कहना बड़ा ही कठिन है। जब देश का उच्च पदस्थ वर्ग ही भ्रष्टाचार के आरोपों के संशय में कैद हो, उसका आचरण लोगों की निगाह में साफ-सुथरा न हो, तो फिर उस देश का भविष्य क्या होगा? इसी कारण डॉ० राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि यदि भ्रष्टाचार को समाप्त करना है तो इसकी शुरुआत उच्च पदस्थ लोगों से होनी चाहिए, पर दुर्भाग्यवश देश का नेतृत्व वर्ग अपने स्वार्थ में अंधा होकर सारा फायदा अपनों के लिए बटोर रहा है। वह चाहे जाति रूप में हो, भाई-भतीजावाद के रूप में हो या क्षेत्रवाद के सन्दर्भ में हो, किन्तु दायरा संकीर्णता व स्वार्थ का है। सभी लोग इसी संकीर्णतावादी नजरिये में कैद हैं। सो 'हमाम में सब नंगे हैं' की तर्ज पर एक दूसरे की कमजोरियों और बुराईयों को अनदेखा कर रहे हैं।

हमारा राष्ट्र विविधताओं से परिपूर्ण है, भारतीय समाज न सिर्फ साहित्य-कला-संस्कृति बल्कि आर्थिक स्तर पर भी इसके कई आयाम हैं। एक ही मॉडल या विचार से पूरे देश को चलाना असम्भव है। देश का किसान जो कि सब के लिए अन्न उगाता है आज वह भी बदहाली के दौर से गुजर रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, पर यह भी सच्चाई है कि मौजूदा रोजगार की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही है। ऐसे में राष्ट्रीय नेतृत्व को अपने विकास की नीतियों, दावों और उपलब्धियों का वस्तुनिष्ठ ढंग से अध्ययन आंकलन और विश्लेषण कर गम्भीरता से प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करना होगा। आर्थिक विकास का मकसद सिर्फ कुछ लोगों द्वारा लाभ कमाना नहीं बल्कि समाज की बेहतरी के लिए काम भी होना चाहिए। आज स्पष्ट रूप से दो वर्ग आमने-सामने हैं। 1. सन्तुष्ट वर्ग 2. असन्तुष्ट वर्ग। सन्तुष्ट वर्ग राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक और धार्मिक हर क्षेत्र में अपना वर्चस्व बना

चुका है, अतः वह यथास्थितिवाद को बनाये रखने के लिए कटिबद्ध है, चाहे इसके लिए कितने भी झूठ का सहारा लेना पड़े। राष्ट्रहित में जरूरी है कि यह वर्ग लोगों को उपदेश देने की बजाय अपनी करनी व कथनी में अन्तर समाप्त करके ईमानदारी, चरित्रवान, कर्मठता, अनुशासन को अपने व्यवहार में लाये। जिस दिन यह सुविधा भोगी वर्ग संकल्पबद्ध होकर त्याग का आदर्श उपस्थित कर देगा देश – समाज की दशा सुधरने में वक्त नहीं लगेगा।

सन्दर्भ

1. भारतीय राजनीतिक विचारक – डॉ० ए०पी० अवस्थी
2. भारत में लोकतन्त्र समस्याएँ व चुनौतियाँ – राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
3. भारतीय राजनैतिक चिन्तन – डॉ० बी० एल० फड़िया
4. डिप्रेसड एक्सप्रेस, मई 2019
5. हिन्दुस्तान न्यूज पेपर – जनवरी 2020
6. विभिन्न टी० वी० चैनल